निर्माण IAS K.D. SIR

# प्रधानमंत्री जी-वन ( जैव ईंधन वातावरण अनुकुल फसल अवशेष निवारण ) योजना PM Ji-Van Yojana (VGF for 2<sup>nd</sup> Generation Ethanol Bio Refineries)

#### संदर्भ

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने प्रधानमंत्री जी-वन (जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना के लिए वित्तीय मदद को मंजूरी दी है।

इसके तहत ऐसी एकीकृत बायो-इथेनॉल परियोजनाओं को, जो लिग्नोंसेलुलॉसिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का इस्तेमाल करती हैं. के लिए वित्तीय मदद का प्रावधान है।

#### वित्तीय प्रभावः

जी-वन योजना के लिए 2018-19 से 2023-24 की अवधि में कुल 1969.50 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय को मंजूरी

परियोजनाओं के लिए स्वीकृत कुल 1969.50 करोड़ रुपये की राशि में से 1800 करोड़ रुपये 12 वाणिज्यिक परियोजनाओं की मदद के लिए, 150 करोड़ रुपये प्रदर्शित परियोजनाओं के लिए और बाकी बचे 9.50 करोड़ रुपये केन्द्र को उच्च प्रौद्योगिकी प्रशासनिक शुल्क के रूप में दिए जाएंगे।

### विवरण:

पहला चरण (2018-19 से 2022-23)- इस अवधि में 6 वाणिज्यिक परियोजनाओं और 5 प्रदर्शन के स्तर वाली परियोजनाओं को आर्थिक मदद दी जाएगी। दूसरा चरण (2020-21 से 2023-24) - इस् अविध में बाकी बची 6 वाणिज्यिक परियोजनाओं और 5 प्रदर्शन स्तर वाली

परियोजनाओं को मदद की व्यवस्था की गई है।

- परियोजना के तहत दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और मदद करने का काम किया गया है। इसके लिए उसे वाणिज्यिक परियोज्नाओं को स्थापित करने और अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने का काम किया गया है।
- ईबीपी कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को मदद पहुंचाने के अलावा निम्नलिखित लाभ भी होंगे-
  - 1. जीवाश्म ईंधन के स्थान पर जैव ईंधन के इस्तेमाल को बढावा देकर आयात पर निर्भरता घटाने की भारत सरकार की परिकल्पना को साकार करना।
  - 2. जीवाश्म ईंधन के स्थार पर जैव ईंधन के इस्तेमाल का विकल्प लाकर उत्सर्जन के सीएचजी मानक की प्राप्ति।
  - 3. बायोमास और फसल अवशेष जलाने से पर्यावरण को होने वाले नकसान का समाधान और लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना।
  - 4. दूसरी पीढी की इथेनॉल परियोजना और बायोमास आपूर्ति श्रृंखला में ग्रामीण और शहरी लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना।
  - 5. बायोमास कचरे और शहरी क्षेत्रों से निकलने वाले कचरे के संग्रहण की समुचित व्यवस्था कर स्वच्छ भारत मिशन में योगदान करना।
  - 6. दूसरी पीढी के बायोमास को इथेनॉल प्रौद्योगिकी में परिवर्तित करने की विधि का स्वदेशीकरण।

योजना के लाभार्थियों द्वारा बनाए <mark>गए इथेनॉल की अनिवार्य रूप</mark> से तेल विपणन कम्पनियों को आपूर्ति, तािक वे ईबीपी कार्यक्रम के तहते इनमें निर्धारित प्रतिशत में मिश्रण कर सके।

- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 2022 तक पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण 10 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इथेनॉल की कीमृत ज्यादा रखने और इथेनॉल खरीद प्रक्रिया को आसान बनाने के तमाम सर्कारी प्रयासों को बावजूद 2017-18 के दौरान इथेनॉल की खरीद 150 करोड़ लीटर ही रही, हालांकि यह देशभर में पेट्रोल में इथेनॉल के 4.22 प्रतिशत मिश्रण के लिए पर्याप्त है।
- इथेनॉल इसी वजह से बायोमास और अन्य कचरों से दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल प्राप्त करने की संभावनाएं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा तलाशी जा रही हैं। इससे ईबीपीं कार्यक्रम के तहत किसी तरह होने वाली कमी को

प्रधानमंत्री जी-वन योजना इसी को ध्यान में रखते हुए लागू की गई है। इसके तहत देश में दूसरी पीढ़ी की इथेनॉल क्षमता विकसित् करने और इस नए क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने का प्रयास किया गया है।

इस योजना को लागू करने का अधिकार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक तकनीकी इकाई सेंटर फॉर हार्ड टेक्नोलॉजी को सौंपा गया है।

इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक प्रोजेक्ट डेवलपरों को अपने प्रस्ताव समीक्षा के लिए मंत्रालय की वैज्ञानिक सलाहकार समिति को सौंपने होंगे।

निर्माण IAS निर्माण IAS निर्माण IAS K.D. SIR

- सिमिति जिन परियोजनाओं की अनुशंसा करेगी उन्हें मंत्रालय के सिचव की अध्यक्षता में संचालन सिमिति द्वारा मंजूरी दी जाएगी।

## पृष्ठभूमि:

- भारत सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम 2003 में लागू किया था। इसके जरिए पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण कर पर्यावरण को जीवाश्म ईधनों के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान से बचाना, किसानों को क्षतिपूर्ति दिलाना तथा कच्चे तेल के आयात को कम कर विदेशी मुद्रा बचाना है।
- वर्तमान में ईबीपी 21 राज्यों और 4 संघ शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत तेल विपणन कम्पनियों के लिए पेट्रोल में 10 प्रतिशत तक इथेनॉल मिलाना अनिवार्य बनाया गया है।
- सरकार ने विद्युत वाहनों (हाइब्रिड वाहनों सिहत) के लिए एक मिशन प्लान अर्थात नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 (एनईएमएमपी 2020) तैयार किया है।
- एनईएमएमपी 2020 में विभिन्न कदमों के जिरये विद्युत एवं हाइब्रिड वाहनों के निर्माण तथा उपयोग में सुविधा के लिए एक रोडमैप (खाका) का उल्लेख किया गया है, तािक बैटरी प्रौद्योगिकी सिहत अन्य तकनीकों में अनुसंधान एवं विकास के लिए सहायता दी जा सके, इन वाहनों की मांग सृजित की जा सके और वर्ष 2020 तक इन वाहनों के निर्माण में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सके।
- 7 मिलियन हाइब्रिड एवं विद्युत वाहनों की बिक्री करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।
- इस मिशन के तहत भारी उद्योग विभाग ने 1 अप्रैल, 2015 से क्रियान्वयन के लिए फेम इंडिया स्कीम (भारत में हाइब्रिड एवं विद्युत वाहनों को त्वरित ढंग से अपनाना एवं विनिर्माण) से अधिसूचित किया है। यह योजना वर्ष 2020 तक के छह वर्षों की अविध के दौरान क्रियान्वित की जानी है, जिसके तहत हाइब्रिड/विद्युत वाहन बाजार के विकास के साथ-साथ इसकी विनिर्माण प्रणाली के लिए सहायता दी जाएगी, तािक निर्धारित अविध के आखिर तक आत्मिनिर्भरता प्राप्त की जा सके। वर्तमान में इस योजना के प्रथम का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसकी अविध 2 वर्षों के लिए निर्धारित की गई थी लेकिन वर्तमान में इसे 1 वर्ष का विस्तार देते हुए इस अविध को 31 मार्च 2018 तक बढ़ा दी गई है।

## प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न-

# प्रधानमंत्री जी-वन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

- 1. इस योजना के तहत वाणिज्यिक स्तर <mark>पर</mark> 12 परियोजनाओं को और प्रदर्शन के स्तर पर दूसरी पीढ़ी के 10 इथेनॉल परियोजनाओं को दो चरणों में वित्तीय मदद दी जाएगी।
- 2. <mark>मौजू</mark>दा नीति के तहत पेट्रोकेमिकल के अलावा मोलासिस और नॉन फीड स्टाक <mark>उत्पादों</mark> जैसे सेलुलोसेस और लिंग्नोसेलुलोसेस जैसे पदार्थों से इथेनॉल प्राप्त करने की अनुमित दी गई है।
- 3. यह योजना चा<mark>र फोकस क्षेत्रों यथा तकनीकी विकास, पायलट परियो</mark>जना, बुनियादी ढांचे के निर्माण में नई गित लाने और मांग सृजन के जरिये क्रियान्वित की जा रही है।

EBE

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

- (a) 1 और 2
- (b) 2 और 3
- (c) 1 और 3
- (d) उपर्युक्त सभी

# मुख्य परीक्षा प्रश्न-

प्रश्न- भारत स्टेज-6 ईंधन मानक को अपनाने, शहरी पर्यावरण प्रदूषण को कम करने और अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल खरीद में कमी लाने के लिए जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना की प्रासंगिकता पर चर्चा करें।

निर्माण IAS निर्माण IAS